Newspaper Clips December 20-21, 2015

December 20

P-2 Business Standard ND 20/12/2015

Move afoot to convert diesel buses into electric

VUAY C ROY

To curb pollution, the ministry of road, transport and highways would introduce 10 lithium ionowered buses or electric buses (retrofitted) for use by state trans-port undertakings by March next year. The ministry is in talks with year. The ministry is in units into state undertakings of Karnataka, Maharashtra, Delhi, etc., to convert their existing diesel into the existing diesel into

CPIT Technologies, a global techology company specialising in T consulting and product engineering, in consultation with the central Institute of Road ransport. Initially, imported bat-

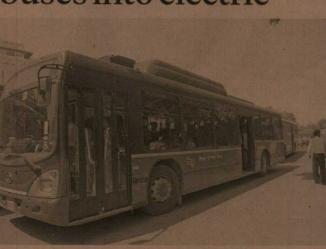
teries would be fitted in buses but later batteries developed by Indian Space Research Organisation (Isro) would be used Narendra Modi on Monday for the purpose, said a ministry official. "Isro is in the process of developing lithium ion battery for the buses. Once it is developed, it will be put in use and the cost will

The technology has been tery. An imported battery costs eloped in India by Pune-based - about ₹25-30 lakh.

The ministry has earmarked about ₹10 crore for the project for developing the technology in India and for converting 12 diesel buses into electric. Another senior official said the

According to him, this was in line with the prime minister's 'Make in India' drive. The top official said the idea was to minimise pollution in the entire country, not just in Delhi.

Electric buses are ideal for urban transport. State transport undertakings purchase about 15,000 buses a year. Out of the total purchases, about 70 per cent are deployed in urban areas. So, if the pilot project becomes successful, it will be a boon to the undertakings, as it would bring down their operational costs as well as pollution.



IIT-Dharwad to start functioning from July

http://www.thehindu.com/todays-paper/iitdharwad-to-start-functioning-from-july/article8009562.ece

Decks have been cleared for the functioning of the Indian Institute of Technology (IIT) here from July 2016, with a three-member technical committee, constituted by the Union Ministry of Human Resource Development, making an announcement on it here on Saturday.

The committee, comprising IIT-Bombay director Devang Khakkar and professors Shivaprasad and Punalkar, visited the Water and Land Management Institute (WALMI) premises where the transit campus would come up.

Later speaking to presspersons, Mr. Khakkar said the new campus was expected to come up in four years on 500 acres at Mummigatti. As per the official communication from the Centre, 120 students would be enrolled for the IIT-Dharwad, he said.

IIT-Bombay would be the mentor for IIT-Dharwad. The HRD Ministry had set up an IIT monitoring cell at IIT-Bombay and the committee members had been designated as officials on special duty to supervise the process of setting up IIT-Dharwad.

The team had given some suggestions to the district administration on developing infrastructure on the transit campus.

May 2016 has been set as the deadline to complete works on the transit campus and the handing over of the premises to IIT-Dharwad, he added.

A three-member technical committee made the announcement on Saturday

Dainik Jagran ND 20/12/2015 P-8

ऑनलाइन निशुल्क उपलब्ध होंगी सीबीएसई की किताबें : ईरानी

केंद्रीय मंत्री ने खिचड़ीपुर स्थित सीबीएसई के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन

 कहा, अगले सत्र से दो शिफ्ट में चलेगा केंद्रीय विद्यालय और 12वीं तक चलेगी कक्षा

 दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी थे मौजूद



खिचड़ापुर स्थित नवानमित कद्रीय विद्यालय का उदघाटन करता शिक्षा मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व अन्य। जागरण

कदम है। छात्र-छात्राओं ने न सिर्फ

बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की जरूरत

है बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री के बेटी

बचाओ, बेटी पढाओ और स्वच्छता

अभियान जैसे अभियानों में भागीदार

बनाना भी जरूरी है। कार्यक्रम के

दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों

का प्रदर्शन कर अतिथियों का मन मोह लिया। अंत में विद्यालय की प्राचार्या नीता खुराना ने सबका हार्दिक आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आयुक्त संतोष कुमार मल्ल, उपायुक्त प्रशासन जीके श्रीवास्तव, उपायुक्त शैक्षणिक उदय नारायण खवाड़े एवं खिचड़ीपुर वार्ड के निगम पार्षद देवेंद्र कुमार, संतोष मिर्धा सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की सभी किताबें सहित पूरी अध्ययन सामग्री ऑनलाइन निशुल्क उपलब्ध रहेंगी। पटपड़गंज के खिचड़ीपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय अगले सत्र से दो पालियों में चलेगा। ये सभी घोषणाएं मुख्य अतिथि केंद्रीय मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी ने विद्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में कीं। उन्होंने फीता काटकर रिमोट से स्कूल भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एवं पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरि ने मंच से ही केंद्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर को दो पालियों में चलाने की मांग की, जिसे स्मृति ईरानी ने स्वीकार कर लिया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन देशहित और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के मसले पर हम सभी एक हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि राजधानी सहित पूरे देश में अधिक से अधिक बच्चों को अच्छी और उच्च स्तरीय शिक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी बात को ध्यान में भरोसा करते हैं। यह एक बड़ी रखते हुए खिचड़ीपुर केंद्रीय विद्यालय उपलब्धि के समान है। को न सिर्फ अगले सत्र से दो पालियों क्षेत्रीय सांसद महोदय महेश गिरि ने में चलाने का निर्णय लिया गया है कहा कि पूर्वी दिल्ली में शिक्षा को बल्कि इसे 12वीं तक भी किया बढ़ावा देने के लिए यह एक सराहनीय

जाएगा। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने क्षेत्रवासियों की तरफ से स्मृति ईरानी का आभार प्रकट किया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेहतरीन शिक्षा के लिए अभिभावक आप सभी पर पूरा

December 21

Economic Times ND 21/12/2015 P-3 CLEANING CAPITAL'S AIR IIT-Kanpur Suggests Use of Eco-friendly Vehicles in Delhi

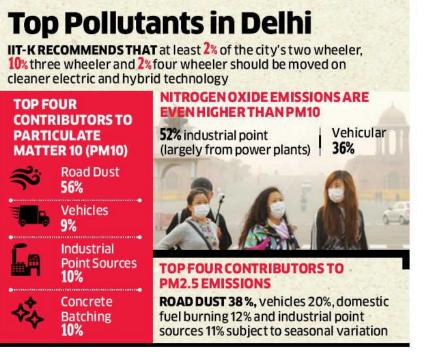
Anubhuti.Vishnoi @timesgroup.com

New Delhi: IIT-Kanpur, which in 2013 has been asked by the Delhi government to study air pollution in the capital, has suggested a slew of measures to clean up the city's air but the odd-even formula is not one of them.

The IIT, which has recently submitted its report on air pollution in Delhi to the Kejriwal government, has suggested that the capital switch increasingly to electric and hybrid vehicles. It has recommended that at least 2% of the city's two-wheelers, 10% of three-wheelers and 2% four-wheelers should be moved to cleaner electric and hybrid technology, says the report which **ET** has reviewed.

It has also called for vacuum sweeping of the city's major roads fourtimes a month, complete stop to use of coal as well as burning of municipal solid waste in the National Capital Region and crop residue in Punjab & Haryana, besides efficient concrete batching and construction waste handling to keep the dust off.

On vehicles, the IIT has suggested retro-fitment of diesel particulate filter, implementation of BS-IV emission standards, usage of ultra-low sulphur fuel containing less than 10 PPM and improved inspection and maintenance of vehicles, as well as instal-



lation of vapour-recovery systems at petrol pumps to control evaporative losses during fuel unloading and refueling. The study calls to ensure that power plants within 300 km of Delhi do not emit Sulphur Dioxide and Nitrogen oxides.

The report, 'Source Apportionment Study of PM2.5 and PM10', details what is ruining the capital's air. The top four contributors to PM10 (particulate matter up to 10 micrometers in size) emissions are road dust (56%), concrete batching (10%), industrial point sources (10%) and vehicles (9%) – these are based on annual emissions which could have seasonal variations. Fugitive road and soil dust re-suspension from ash pond and emission from concrete batching will be significantly lower in winter than during summer months.

Top four contributors to PM2.5 emissions are road dust (38%), vehicles (20%), domestic fuel burning (12%) and industrial point sources (11%), subject to seasonal variation.

Economic Times Hindi ND 21.12.2015 P-8

टेक्नोलॉजी प्रॉडक्ट फर्म खोलने में IIT स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट

शाश्वति शंकर मुंबई आईआईटी बॉम्बे में इलेक्टिकल इंजीनियरिंग के स्ट्डेंट और कैश-बैक प्लेटफॉर्म dealwithus.in के फाउंडर कमल कुमावत का मानना है कि स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल प्रॉडक्ट्स बनाने वाली स्टार्टअप्स पर फोकस करना बेहतर रहेगा क्योंकि सर्विसेज से जुड़े स्टार्टअप्स में ग्रोथ की ज्यादा संभावना नहीं है।

कमल (22) ने बताया, 'मेरे विंग में 10 रूम हैं और उनमें से चार में सविंसेज से जुड़ी स्टार्टअप्स हैं। उनमें से एक बंद हो चुकी है और अन्य को फंडिंग हासिल करने में दिक्कत हो रही है। सविंसेज से जडी

स्टार्टअप शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मार्केट आईआईटी बॉम्बे के (एसआईएनई) के पास में पहले ही काफी भीड़ है।' स्टूडेंट्स और एंजल

उनकी इस राय से कैम्पस में इनवेस्टर्स का कहना है कि और फिनटेक स्टार्टअप्स मौजूद आंत्रप्रेन्योर बनने की इच्छा सर्विसेज से जुड़े स्टार्टअप्स की संख्या अधिक है। रखने वाले बहुत से अन्य छात्र भी की संख्या में कमी आई है सहमत हैं। आईआईटी बॉम्बे के और टेविनकल प्रॉडक्ट से की मदद कर रही है। स्टडेंट्स और एंजल इनवेस्टर्स जुड़ी स्टार्टअप्स बढ़ी हैं का कहना है कि सर्विसेज से जुडे

स्टार्टअप्स की संख्या में कमी आई है और टेक्निकल प्रॉडक्ट से जुड़ी स्टार्टअप्स बढ़ी हैं। कैम्पस में प्री-इनक्यूबेशन सपोर्ट सेंटर, देसाई सेठी सेंटर फॉर आंत्रप्रेन्योरशिप की सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अपर्णा राव ने बताया, 'हम हेल्थकेयर सेगमेंट में आइडिया पर काम होता देख रहे हैं। स्टूडेंट्स ने महिलाओं में ज्यादा जोखिम वाली प्रेग्नेंसी का पता लगाने

के लिए डिवाइस, निमोनिया की पहचान के लिए मोबाइल ऐप और अंडरग्राउंड माइंस को पकडने के लिए डिफेंस डिवाइसेज बनाए al'

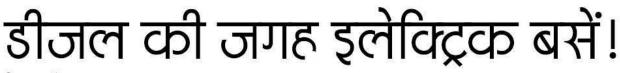
राव ने कहा कि स्टूडेंट्स ने कुछ अन्य आइडिया और कॉनसेप्ट भी पेश किए हैं. जिन पर काम चल रहा है। इनमें रिसाइक्लिंग के जरिए वेस्ट को कम करना, मौजुदा लैपटॉप को अपग्रेड और मॉडिफाई करना. वाईफाई कनेक्शंस के इस्तेमाल से कॉन्सर्ट में साउंड क्वॉलिटी को बेहतर बनाना और मोबाइल फोन को टेम्परेरी स्पीकर में बदलने वाले वियरेबल डिवाइस शामिल है।

सोसायटी फॉर इनोवेशन एंड

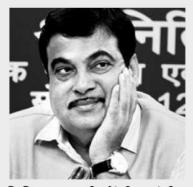
आं त्र प्रेन्यो र शिप बायोमेडिकल, क्लिनटेक अभी यह 26 स्टार्टअप्स एसआईएनई की सीओओ पायोनी भट ने बताया.

'बायोमेडिकल स्टार्टअप्स की संख्या इतनी बढ़ी है कि हम अगले छह महीनों में एक बायोइनक्यूबेटर शुरू करने की योजना बना रहे हैं।' इनक्यूबेटर में आधी से ज्यादा स्टार्टअप्स को इस वर्ष की शुरुआत में एंजल इनवेस्टमेंट्स हासिल हुए थे। उन्होंने बताया कि हार्डवेयर से जुड़ी स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने में समय लगता है।

Business Standard Hindi ND 21.12.2015 P-4



2016 में दिल्ली से थाईलैंड सड़क मार्ग से



नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

लक्ष्य को मार्च 2016 तक हासिल कर लेंगे।' मंत्री ने कहा, ' जिस तरह से आप दिल्ली से मुंबई तक कार में यात्रा करते हैं, उसी तरह आप थाईलैंड पहुंच सकेंगे। उम्मीद है कि यह अगले साल तक संभव होगा। यह एक क्रांतिकारी काम है, लोग अभी विश्वास नहीं करेंगे।' भाषा

इससे न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में प्रदूषण कम होगा। शहरी यातायात के लिए इलेक्ट्रिक बसें आदर्श हैं।

विभिन्न राज्य परिवहन निगम साल में करीब 15,000 बसें खरीदती हैं। कुल खरीद में से करीब 70 प्रतिशत का आवंटन शहरी इलाकों में होता है। इस तरह से अगर यह प्रायोगिक परियोजना सफल होती है तो यह निगमों की तस्वीर बदल देगी। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि परिचालन लागत में भी कमी आएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि भारत व थाईलैंड को सड़क मार्ग के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। यही नहीं, उनको भरोसा है कि 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क के सपने को नए साल यानी 2016 में जमीन पर उतारा जा सकता है।

नए साल के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अब सड़क निर्माण क्षमता को 100 किलोमीटर प्रतिदिन की ऊंचाई पर ले जाना है। मंत्री ने कहा, 'हम इस समय 18 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़क बना रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हम 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण के अपने पूर्व घोषित

मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए करीब 10 करोड़ रुपये का बजट बनाया है, जिससे भारत में यह तकनीक विकसित की जाए और 12 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जा सके।

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केपीआईटी टेक्नोलॉजिज द्वारा विकसित दो प्रोटो टाइप बसों को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हरी झंडी दिखाएंगे। उनके मुताबिक यह प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि

विजय रॉय नई दिल्ली, 20 दिसंबर

प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले साल मार्च तक 10 लीथियम आयन से चलने वाली यानी इलेक्ट्रिक बसें राज्य परिवहन निगमों को सौंपेगा। इसके लिए मंत्रालय कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों के निगमों से बातचीत कर रहा है, जिससे मौजूदा डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जा सके।

यह तकनीक आईटी कंसल्टिंग और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में पुणे विशेषज्ञता वाली की केपीआईटी टेक्नोलॉजिज ने केंद्रीय सडक परिवहन इंस्टीट्यूट के साथ विकसित की है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में बसों में आयातित बैटरी का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन बाद में भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान (इसरो) द्वारा विकसित बैटरी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा, 'इसरो बसों के लिए लीथियम आयन बैटरी विकसित करने की प्रक्रिया में है। एक बार ऐसा हो जाने पर इसकी लागत में बहुत ज्यादा कमी आएगी।' अधिकारी ने कहा कि इसरो के अलावा और आईआईटी खडगपुर आईआईटी मद्रास भी लीथियम आयन बैटरी पर काम कर रहे हैं। आयात की गई एक बैटरी की लागत 25-30 लाख रुपये होती है।

IIM Bill must create a level playing field

If IIMs are allowed to grant degrees instead of diplomas, then the newer IIMs, some of which are ranked lower than private institutions, will have an edge over the latter

http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/iim-bill-must-create-a-level-playing-field.html

As businesses across the globe eye the Indian market and the Government of India endeavor to not only make India a manufacturing hub but also to make the country's economic growth more inclusive, the demand for professional managers will increase many folds. This will make making management education more important than ever before. It is in this context that The Indian Institute of Management Bill, 2015, that has been listed for consideration by Parliament in this session must be viewed.

The Bill has already sparked a debate, which is being led by three major players in management education in India — the old and reputed IIMs (IIM-Ahmedabad, IIM-Bangalore and IIM-Calcutta), the new IIMs (such as the ones in Rohtak, Ranchi and Kashipur) and private institutes. The Bill proposes that the IIMs will be allowed to grant degrees instead of diplomas. As a result, the Post Graduate Diploma in Management will become a Masters in Business Administration and the fellowship programme will become a PhD.

The new IIMs appreciate this proposal as they feel that granting degrees will help them build their brand and make their courses more attractive. But the established IIMs oppose this move. They argue that they already have an excellent reputation due to high standards of education and its irrelevant whether they grant a degree or diploma.

The private management institutes are opposing the Bill since they are the worst hit. Allowing all IIMs to grant degrees may have an adverse effect on their popularity as they will not be able to grant degrees themselves. This may even put their existence in jeopardy.

Some private institutes like FORE School of Management (to which the author is affiliated), International Management Institute, Management Development Institute, SP Jain Institute of Management and Research, Narsee Monjee Institute of Management Studies and Symbiosis Institute of Business Management rank above some of the new IIMs.

These private institutes have quality infrastructure, admirable course curriculum and faculty, affordable fee structure and location, along and outstanding track record and remarkable placements. With the new IIMs being able to grant MBA degrees instead of diplomas, it is probable that students will make their preferences based on the nature of certification rather than institute rankings. The courses run by private institutes will lose their sheen once all the IIMs begin to award degrees.

The argument put forth by the old IIMs(Ahmedabad, Bangalore and Calcutta) is also untenable: If a universal policy is being framed for management education then all institutions, irrespective of their market standing and brand, ought to be put under the same umbrella. However, this will change the game in favour of the new IIMs against the private institutes which are offering quality management education by jeopardizing the latter's diploma programmes.

Allowing IIMs to grant degrees will compromise the position private institutions. There must be a level-playing field for everyone. The Government should draft a Management Education Bill rather than an 'IIM Bill' to cover all management institutes — be the Government-run, autonomous or private-owned.

(The writer is a professor at FORE School of Management)

IIM, IIT & ISI join hands to offer business analytics course

Hindustan Times (Kolkata)

From the academic session starting 2016, IIM Calcutta, IIT Kharagpur and Indian Statistical Institute (ISI) are coming together to offer a unique course.

The fee for the two-year business analytics course is Rs 16.2 lakh.

The post graduate diploma in business analytics (PGDBA), being offered by these coveted institutes, aims at creating professional business analytics by giving students a cutting edge educational experience.

And at the end of two years, the degree will be jointly awarded by these three institutions.

In its first year of commencement, the course has seen tremendous response from the student fraternity, with over 1,000 applicants flocking for it. The exposure provided by the institutes collectively is highly coveted in today's times of competitive analysis.

PGDBA is a two-year full time residential diploma programme aimed at creating business analytics professionals employable by leading Indian and foreign fir ms. "This programme is designed for those who have an analytical mindset, are interested in tackling challenging business problems, and possess an inclination towards mathematics," said an official at IIM Calcutta.

Some of the salient features of the programme include courses taught by reputed faculty members at the campuses of three globally renowned institutes, hands-on business analytics training at a related company, continuous interaction with industry leaders throughout the diploma programme and the availability of placement opportunities.

The two-year course would cost the students Rs 16.2 lakh. The course will be run in a unique way. The programme is divided into semesters. This would ensure that the students spend equal amount of time in all the three campuses for the first three semester. The fourth semester will be spent as an industry intern.

While IIM Calcutta will teach the application of analytics in functional areas, IIT Kharagpur will enlighten the students about the technology aspect of analytics. Whereas ISI will concentrate on statistical and machine learning theories of analytics.

While the course will be conducted in residential mode by IIM Calcutta and IIT Kharagpur, at ISI it will not be mandatory to be a boarder.

Students with good CAT, GRE, GATE and GMAT scores or those selected for any masters level entrance examinations conducted by ISI can apply.

दिल्ली के सुपर कंप्यूटर की दुनिया में धाक, जानिए कौनसे नंबर पर है_{- नई}

http://www.patrika.com/news/computer/iit-delhi-supercomputer-is-the-116-fastest-globally-1147757/

दिल्ली। कैलिफोर्निया की टेक कंपनी एनवीडिया के जीपीयू वाला आईआईटी दिल्ली का सुपर कंप्यूटर दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर�की�लिस्ट में 166वें नंबर पर है। एनवीडिया ने 2012 में आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का ऐलान किया था। यह भारत का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है।

दिलचस्प बात यह है कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में 70 सिस्टम में एनवीडिया टेस्ला के बनाए हुए हैं। 860 टेराफ्लॉप्स का यह सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर आईआईटी का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जिसे टॉप डेवलपर्स और रिसर्चर्स यूज करते हैं।

लैपटॉप पर गिर गया है पानी या चाय, तो उसें फिर से ऐसे बनाएं परफेक्ट

इस कंप्यूटर में एनवीडिया का कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्ट और ओपेन एकस्लरेशन का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसके जरिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जेनरल प्रोसेसिंग के लिए सीयूडीए एनेबल्ड ग्राफिक्स यूज करते हैं। खास बात यह है कि सीयूडीए और ओपेन एसीसी दूसरे सुपर कंप्यूटर के मुकाबले सस्ते हैं।

आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर सर्विस के एसोशिएट हेड सुबोध कुमार ने कहा हम सबसे फास्ट जीपीयू सेंट्रीक एचपीसी कलस्टर से काफी खुश हैं। फिलहाल यह सिस्टम कई रिसर्चर्स के लिए एक्टिव है और वो इसे यूज कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि रिसर्चर्स को यह अगले लेवल के रिसर्च और प्रोब्लम सोल्व करने में काफी योगदान देगा। इसके अलावा इससे मोलिक्यूलर सिस्टम, बायोलॉजी, नैनो सिस्टम औक दूसरे रिसर्च में भी मदद मिलेगी।

Need to harness solar energy to fight climate change: PM Modi

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/need-to-harness-solar-energy-to-fight-climate-change-pm-modi/articleshow/50267117.cms

NEW DELHI: Terming the negative impact of environment pollution as a challenge, Prime Minister Narendra Modi today said there is a need to harness solar energy.

"Discussions of environment have been taking for long, but for the last few years, its negative impact has been felt on normal human lives... There is a challenge before the mankind to find a solution to this problem," Modi said.

He was speaking at an event where he flagged off an electric bus, gifted by the Road Transport and Highways Ministry to Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, to ferry MPs at Parliament.

He was clear that the countries are going to work to harness solar energy.

Referring to the recent CoP-21 summit in Paris, Modi highlighted two significant initiatives -- Mission Innovation launched jointly by the US, France and India, with the help of the Bill and Melinda Gates Foundation, on development of green technologies and the creation of the International Solar Alliance of countries with abundant sunlight.

The headquarters of this alliance will be in Delhi, the Prime Minister said.

"There are 122 nations which get the benefit of sunrays for more than 300 days in a year. With India's initiative, an organization of such nations has been formed," Modi said.

Resolutions in Paris by world leaders include work on innovation to get fossil fuel-free energy, Modi added.

"US, France and India have taken initiatives for innovation. The Bill Gates Foundation has also been associated with it. A positive result will come by," he hoped.

Congratulating Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari on his contribution to environment and technology leading to the refurbished bus with no pollution, the PM suggested that the technology can be used in public transport as well.

Such buses would "not only significantly contribute in minimising pollution, but would encourage younger generation to come into research and making of batteries".

"MPs will benefit from it. New generation can come forward in 'Start up India' and 'Stand up India' and contribute to initiatives like making batteries," he said.

Modi saw a need for research to enhance battery life and said such initiatives under 'Make in India' will not just benefit the country, but the whole world as well.

Environment Minister Prakash Javadekar was also present.

The Prime Minister tweeted, "This bus here (launched today)... is not making noise, and scope of pollution also does not arise."

He said in another tweet: "In Paris, during CoP21, leaders of the world came together and focus was placed on innovation (in energy)."

The PM inspected the retrofit electric bus, which is a conversion of a diesel bus into a battery-operated electric one, and handed over the key to the Speaker Mahajan.

On the occasion, Gadkari said the bus is under 'Make in India' initiative and another 20 are part of the pilot project.

He also lauded the role of ISRO scientists who have developed the indigenous lithium ion battery at a cost of barely Rs 5-6 lakh in comparison to a huge Rs 50 lakh for the imported ones as the patent is being registered.

The bus has been launched with a commitment to contributing to the 'Swatch Bharat' initiative of the government, with a broader objective to make India pollution-free.

Gadkari said a policy to promote environment-friendly ethanol, bio-diesel, gas and CNG will be announced in this Parliament session as most older diesel buses are running on BS-II and BS-III engines, which are seen as highly polluting.

The government is also making regulations for allowing Flex Fuel vehicles that give a choice to users to choose fuel.

"The government wants to convert about 1.5 lakh state transport corporation buses into electric ones. We would like to convert buses operated by STUs in the next two years to electric mode. We are exploring innovative low-cost funding for this project," he said.

Gadkari said the government is committed to providing clean air for citizens and will take steps to introduce only ecofriendly vehicles for public transport as one such bus will save the environment from 48,000 kg of CO2.

"At the same time, we need to address problems of the existing vehicles by converting them into electric or hybrid vehicles," the minister said.

"I am sure with the increased volumes, Made in India technology buses will be available for retrofit below Rs 40 lakh."

He pegged the savings from the introduction of such buses at close to Rs 10 lakh per annum in diesel costs.

He said the steps were bound to help in reducing the country's dependence on imported crude and the government has already introduced stringent emission norms for BS-V and BS-VI vehicles and dates for implementation have been advanced.

In Lok Sabha, the Minister of State for Parliamentary Affairs Rajiv Pratap Rudy thanked Gadkari for the pollution-free electric bus initiative.

Also, Vinayak Raut of Shiv Sena congratulated the minister for piloting the project and hoped that the country would benefit.

As part of efforts to curb pollution, the Road Transport and Highways Ministry is in the final stage of completing a pilot project under which 20-refurbished electric buses will be handed over to select State Transport Corporations by March 2016.

The two buses for lawmakers of which one was gifted by the Prime Minister today are the first prototype developed by KPIT Pune with consultations from Central Institute of Road Transport and the technology has been wholly-developed in India.

The Road Transport and Highways Ministry is in touch with State Transport Corporations from Maharashtra, Karnataka and Delhi for conversion of 20 diesel buses into electric ones.

Indian Space Research Organisation, IIT Kharagpur and IIT Madras are already in the process of developing such lithiumion batteries.